



नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री



योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

बढ़ चला उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की ओर

जन-अपेक्षाओं को साकार करने के 6 माह



सबका साथ-सबका विकास



मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी को आवास का स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए। (20 जून, 2017)

नई कार्य-संस्कृति



भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से गुजरता है, क्योंकि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश विश्व के पाँचवें बड़े राष्ट्र के बराबर है। इतनी बड़ी आबादी के विकास और प्रगति की आकांक्षाएं हिमालय के शिखरों की तरह ऊँची हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए प्रचण्ड बहुमत की सरकार बनायी।

छह महीने पहले 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार ने शपथ ली। प्रचण्ड बहुमत की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने पहले 100 दिन के काम-काज में ही स्पष्ट कर दिया कि उसे जनता की अपेक्षाओं और कसौटी का पूरा पता है और प्रगतिशील बदलाव के लिए कार्य करना है। प्रदेश के सरकारी विभागों में काम-काज कैसे चल रहा है और उनके पास विकास की क्या कार्ययोजना है—इसे जानने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के प्रस्तुतियों को अपने मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों के साथ परखा। फिजूलखर्ची व



के अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा समूह 'ख' के अराजपत्रित पदों तथा समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के सभी पदों की भर्ती में पक्षपात एवं भेदभाव की गुंजाइश को समाप्त करने के लिए इनके चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। बालिका शिक्षा एवं महिला सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। अक्टूबर 2018 तक पूरे प्रदेश को खुले में शौचमुक्त करने का भगीरथ प्रयास किया जा रहा है। यह एक ऐसा कार्य है, जिसके बारे में अब तक किसी सरकार ने सोचने की हिम्मत ही नहीं की। ये सब प्रयास सरकार की नई कार्य संस्कृति का बयान करते हैं—

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि, न मनोरथैः।

नहि सुसुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।।

मा. मुख्यमंत्री राज्य में अमन—चैन एवं विकास के लिए प्रतिदिन स्वयं 18 घण्टे उद्यमशील रहते हैं। खुद कड़ी मेहनत करते हैं, इसीलिए सबको सही दिशा में कार्य के लिए प्रेरित भी करते हैं। 'कार्य कठिन है इसीलिए करने योग्य है।' इस भावना से वह राज्य की जनता की सेवा में अहर्निश समर्पित हैं।



अमन के वास्ते : कानून-व्यवस्था



- ◆ गुण्डों, माफियाओं, अपराधियों तथा अराजक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु कार्य प्रणाली में आमूलचूल बदलाव।
- ◆ पुलिस की मित्र-छवि विकसित करने एवं अपराधियों पर कठोर कार्यवाही करने के उद्देश्य से प्रतिदिन चेकिंग हेतु "फुट पेट्रोलिंग" की व्यवस्था।
- ◆ प्रदेश में अवैध गतिविधियों में लिप्त 1385 व्यक्तियों के विरुद्ध 766 अभियोग पंजीकृत करते हुए 1143 के विरुद्ध कार्यवाही।
- ◆ प्रदेश में 54 अपराधियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरुद्धि आदेश तथा 1145 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत। 9973 अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही।



- ◆ 10320 गंभीर वादों में अपराधियों को सजा, जिसमें 1033 वादों में 2076 अभियुक्तों को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा सम्मिलित है।
- ◆ 20 मार्च से 14 सितंबर के बीच प्रदेश में पुलिस व बदमाशों के बीच हुई 430 मुठभेड़ में अब तक 17 दुर्दान्त अपराधी मारे गये, जबकि 1106 को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया गया। 868 पुरस्कार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल। इन मुठभेड़ों में 88 पुलिस कर्मी घायल हो गये तथा सब-इन्स्पेक्टर जयप्रकाश सिंह जो चित्रकूट जनपद में पदस्थ थे, वीरगति को प्राप्त हुए। गैंगेस्टर एक्ट के तहत 69 बदमाशों की अपराध के जरिए अर्जित की गई अवैध संपत्ति सीज। छह भू-माफिया की करीब 35 करोड़ की संपत्ति सीज।
- ◆ नवरात्र, दशहरा तथा दीपावली के त्योहारों की भांति, सौहार्द एवं उल्लासमय वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था।

- ◆ एसटीएफ द्वारा पेट्रोल पम्पों पर इलेक्ट्रानिक चिप लगाकर घटतौली करने का भन्डाफोड।
- ◆ एन्टी रोमियो स्क्वायड के माध्यम से छात्राओं कामकाजी महिलाओं तथा सार्वजनिक स्थलों पर आने जाने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु सघन अभियान। 2011 शरारती तत्वों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गयी। 1054 अभियोग पंजीकृत किये गये तथा 6,30,786 लोगों को सचेत किया गया।
- ◆ सतर्कता विभाग द्वारा 51 प्रकरणों में खुली जाँच के आदेश। 15 लोक सेवकों को ट्रेप कराया गया।
- ◆ लोक सेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने तथा उनके विरुद्ध प्राप्त कदाचार-अनाचार एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों में कठोर कार्यवाही।

कारागार

- ◆ जिला कारागार हरदोई, देवरिया, गोरखपुर, मैनपुरी, की मुख्य प्राचीर का निर्माण कार्य पूर्ण।
- ◆ अलीगढ़, एटा, बान्दा, देवरिया, झाँसी तथा बुलन्दशहर में जैमर लगा दिया गया है तथा 06 अन्य कारागारों में जैमर लगाने की भी स्वीकृति।
- ◆ केन्द्रीय कारागार आगरा, जिला कारागार मुजफरनगर, वाराणसी, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, मेरठ तथा गौतमबुद्धनगर में सोलर पावर बैकअप सिस्टम की स्थापना।

- ◆ जनपद ललितपुर में 4500 बन्दी क्षमता की उच्च सुरक्षा कारागार के निर्माण हेतु 100 एकड़ भूमि चयनित ।
- ◆ मोबाइल फोन जैमर को निरन्तर क्रियाशील रखने हेतु नवम्बर, 2017 तक 17 कारागारों में सोलर पावर बैकअप सिस्टम स्थापित कर दिया जायेगा ।
- ◆ 31 मार्च, 2018 तक सभी कारागारों में डीप सर्च मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था ।
- ◆ 67 कारागारों तथा 69 मा0 जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग ईकाई स्थापित । मार्च, 2018 तक शेष 03 कारागारों तथा 04 मा0 जनपद न्यायालयों में स्थापना का लक्ष्य ।
- ◆ "नमामि गंगे जागृति यात्रा" का 09 अगस्त से 06 सितम्बर, 2017 तक हरिद्वार से बलिया तक का आयोजन ।
- ◆ प्रधानमंत्री सुरक्षाबीमा योजना, दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 20831 होमगार्ड्स आच्छादित ।
- ◆ यातायात तथा जाम समाप्त करने सम्बन्धी ड्यूटी हेतु 3000 से अधिक होमगार्ड्स प्रतिस्थापित किये जा रहे हैं ।



लोक निर्माण : ताकि बढ़ता रहे प्रदेश



- ◆ लगभग 80 हजार कि०मी० सड़क को बरसात के पूर्व गड़्डामुक्त किया गया।
- ◆ टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू। लोक निर्माण विभाग की हेल्पलाइन नं० 1800 121 5705 प्रारम्भ।
- ◆ झांसी से जालौन-उरई-बेला होते हुए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे चार लेन राष्ट्रीय मार्ग के निर्माण की सहमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी। झांसी-चित्रकूट-इलाहाबाद-राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में परिवर्तित करने का निर्णय। वर्तमान में दो लेन पेड बनाया जा रहा है, बाद में फोर लेन निर्माण कराया जायेगा।
- ◆ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश में जो गांव अभी तक संपर्क मार्ग से नहीं जुड़े हैं उन्हें चिन्हित करते हुए पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की कार्य-योजना प्रगति पर। प्रदेश के सभी तहसील एवं ब्लाक मुख्यालयों को 2 लेन रोड से जोड़ा जाना प्रस्तावित। बड़ी नदियों पर सेतुओं का निर्माण की कार्य-योजना।
- ◆ राष्ट्रीय मार्ग-2 एवं राष्ट्रीय मार्ग-11 के मध्य 99 कि०मी० की लागत से चार लेन राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण एवं रेडियल मार्ग सहित गोवर्धन के चारों ओर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग चार लेन को रू० 4645 करोड़ की लागत से बनाये जाने का निर्णय लिया गया।
- ◆ जनपद सन्तकबीर नगर में खलीलाबाद-गोरखपुर सेक्शन पर उपरिगामी सेतु का निर्माण पूर्ण। जनपद कानपुर में गोविन्दपुरी रेलवे स्टेशन के पास उपरिगामी सेतु का निर्माण पूर्ण। जनपद उन्नाव में रेलवे स्टेशन के निकट लखनऊ-कानपुर रेल मार्ग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण पूर्ण। जनपद हाथरस में टूण्डला-गाजियाबाद पर दो लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण पूर्ण। जनपद हाथरस में सासनी-जलेसर मार्ग दो लेन उपरिगामी सेतु का निर्माण पूर्ण। जनपद जे०पी० नगर (अमरोहा) में अमरोहा-अटारसी मार्ग पर अमरोहा-काफूरपुर के रेल सेक्शन पर दो लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण पूर्ण। जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग पर अगवानपुर पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण पूर्ण।



शिक्षा : बच्चों का अधिकार – कर्तव्य हमारा



- ♦ जुलाई से 31 अगस्त तक “स्कूल चलो अभियान” का संचालन पूरे प्रदेश में किया गया जिसमें विद्यालय, विकास खण्ड, जनपद स्तर तथा राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- ♦ मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं जनपद—लखनऊ, गोरखपुर व हापुड़ में “स्कूल चलो अभियान” का शुभारम्भ। अब तक कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय विद्यालयों में कुल 1.53 करोड़ नामांकन कराये जा चुके हैं।
- ♦ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 के अन्तर्गत लगभग 27000 बच्चों को उनके घर के निकट निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश कराया गया।
- ♦ समस्त शासकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1—8 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण लगभग पूर्ण। ससमय पुस्तकों के वितरण की कार्यवाही अभूतपूर्व।
- ♦ छात्र—छात्राओं को निःशुल्क आकर्षक यूनिफॉर्म का भी वितरण लगभग पूर्ण। छात्र—छात्राओं को निःशुल्क बैग का वितरण एवं जूता मोजा व स्वेटर भी प्रदान किया जा रहा है।
- ♦ दिव्यांग बच्चों के लिए 455 चिकित्सा परीक्षण शिविर, निःशुल्क उपकरण और उपस्कर वितरित करने के लिए 259 शिविर आयोजित किये जायेंगे। दृष्टिबाधित 3359 बच्चों की शिक्षा के लिए ब्रेल पाठ्य—पुस्तकों के सेट की व्यवस्था की गयी है।



माध्यमिक शिक्षा

- ◆ नकल पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 में संशोधन। 15 वर्षों में पहली बार नकल मुक्त परीक्षा का आयोजन।
- ◆ अप्रैल, 2018 से 166 पं० दीनदयाल उपाध्याय माडल राजकीय इण्टर कालेजों के संचालन का निर्णय।
- ◆ हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों की मान्यता के लिए पारदर्शी ऑन-लाईन व्यवस्था।
- ◆ बोर्ड परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण की व्यवस्था।
- ◆ प्रतिनियुक्त के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की माध्यमिक विद्यालयों में तैनाती की प्रक्रिया प्रारम्भ।
- ◆ उ०प्र० की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी को स्नातकोत्तर स्तर तक रू० 2000 (दो हजार रुपये) प्रतिमाह/प्रति छात्र की दर से पं० दीनदयाल उपाध्याय विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था।
- ◆ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी राजकीय इण्टर कालेजों में सह-शिक्षा की व्यवस्था।
- ◆ राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों को पारदर्शी तरीके से भरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन।
- ◆ माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. इलाहाबाद के पाठ्यक्रम में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के अनुरूप संशोधनोपरान्त नवीन पाठ्य-पुस्तकों का अप्रैल, 2018 से प्रचलन।



- ◆ शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु उ.प्र. शिक्षा सेवा अधिकरण का गठन।
- ◆ ऑनलाइन ड्रफ्टीकेट अंक पत्र/प्रमाण पत्र की व्यवस्था की कार्यवाही प्रारम्भ।
- ◆ उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सी.बी.एस.ई. तथा आई.सी.एस.ई. से कक्षा 10 एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण प्रदेश के 147 छात्र/छात्राओं को मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा एक-एक लाख रुपये तथा एक-एक टैबलेट प्रदान कर सम्मानित किया गया।
- ◆ शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रथम बार मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के चयनित अध्यापकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- ◆ 1847 राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई बालिका आत्मरक्षा कार्यक्रम का संचालन।
- ◆ 400 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा में बोलने की दक्षता विकास हेतु कार्यक्रम का संचालन।
- ◆ राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-9 के कमजोर 28,379 छात्र-छात्राओं को अंग्रेजी, गणित, एवम् विज्ञान में एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था।

उच्च शिक्षा

- ◆ सभी लड़कियों को अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के अन्तर्गत ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी।
- ◆ शुचितापूर्ण नकल विहीन परीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु अनुचित साधनों का निवारण नियमावली, 2017 के प्रख्यापन की कार्यवाही प्रचलित।
- ◆ महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।





- ◆ सभी राजकीय महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में ई-लाइब्रेरी की स्थापना ।
 - ◆ महाविद्यालयों के ऑन-लाइन सम्बद्धता हेतु साफ्टवेयर का विकास 30 नवम्बर, 2017 तक करके इसे 20 दिसम्बर, 2017 तक विश्वविद्यालय को प्रशिक्षण सहित उपलब्ध करा दिया जाएगा ।
- शैक्षिक सत्र 2018-19 से निम्नांकित शैक्षिक कैलेंडर लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है :-
1. 10 जुलाई, तक स्नातक कक्षाओं में पूर्व में प्रवेशित छात्रों का अध्यापन कार्य प्रारंभ किया जाय ।
 2. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु बी.एड. की समय सारिणी को अंगीकृत किया जाय तथा प्रवेश प्रक्रिया 30 जून तक पूर्ण कर ली जाय । प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात 09 जुलाई, 2018 को शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया जाय ।
 3. परास्नातक प्रथम वर्ष का प्रवेश 31 जुलाई, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाय तथा अगस्त के पहले सोमवार से शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया जाय ।
 4. प्रयोगात्मक परीक्षाएं दिनांक 15 जनवरी, 2019 से 28 फरवरी, 2019 तक पूर्ण कर ली जायें ।
 5. 01 मार्च, 2019 से मुख्य परीक्षाएं प्रारंभ की जायें तथा 60 दिन में परीक्षाएं सम्पन्न करा ली जायें ।
 6. 25 जून, 2019 तक समस्त परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये जायें ।
 7. सेमेस्टर परीक्षाओं की समय सारिणी विश्वविद्यालय अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे ।
- ◆ राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्राचार्यों से 33 स्नातकोत्तर प्राचार्य पदों पर पदोन्नति ।
 - ◆ अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत 155 प्रवक्ताओं का आमेलन करते हुए नियुक्ति ।
 - ◆ उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ.प्र. इलाहाबाद द्वारा विज्ञापन संख्या-46 के अन्तर्गत चयनित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्राफेसर के लगभग 870 पदों पर आसन व्यवस्था प्रदान की गई है ।
 - ◆ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना तथा कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में समितियों का गठन ।



तरक्की को चाहिए एक नई ऊर्जा



- ◆ विद्युत आपूर्ति में भेदभाव को समाप्त करते हुये प्रदेश के सभी स्थानों पर एक जैसी विद्युत आपूर्ति शिड्यूल लागू। शहरों की भाँति ग्रामीण क्षेत्रों में भी रात में निर्बाध विद्युत आपूर्ति। जनपद मुख्यालय को 22 से 24 घंटे, तहसील मुख्यालय को 20 घंटे एवं गांवों को 18 घंटे बिजली की आपूर्ति।
- ◆ ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को भी निःशुल्क विद्युत कनेक्शन की सुविधा।
- ◆ सभी को बिजली देने के लिए भारत सरकार के साथ 24 घंटे पावर फॉर आल एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित।
- ◆ 05 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शन के लिये इस्टीमेट की प्रथा समाप्त कर आसान किशतों में विद्युत संयोजन देने के लिये "सुगम संयोजन योजना" लागू। नये 03 कनेक्शन की माँग होने पर एक विद्युत पोल लगाकर विभागीय खर्चे पर विद्युत लाइन का विस्तार।
 - ◆ गत 05 माह में ही 16.29 लाख नये कनेक्शन दिये गये। माह दिसम्बर, 2018 तक हर घर को विद्युत कनेक्शन देने हेतु से सभी छूटे हुये मजरों का प्रदेश व्यापी सर्वे कार्य प्रगति पर।
 - ◆ 26,999 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण। 8485 अतिभारित ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि।
 - ◆ पहली बार उपभोक्ताओं को घर बैठकर स्वयं विद्युतबिल सृजित करने तथा भुगतान इन्टरनेट से करने की सुविधा। मोबाइल एप्प द्वारा विद्युत बिल एवं आपूर्ति सम्बन्धित शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध।
 - ◆ पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत सभी विकास खण्डों के मुख्य बाजारों में सोलरस्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना का निर्णय।
 - ◆ इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी एवं बहराइच के 1000 प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल एवं पंखे की सुविधा हेतु सोलर आर. ओ. प्लांट की स्थापना का निर्णय।

- ◆ किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ में 3000 व्यक्तियों के लिए सोलर स्टीम कुकिंग प्लाण्ट की स्थापना ।
- ◆ 120 मेगावाट क्षमता की यूटिलिटी स्केल की 7 सौर विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापना पूर्ण । 46.5 मेगावाट क्षमता की बायोमास आधारित 2 विद्युत परियोजनायें अधिष्ठापित । 31 सरकारी / अर्द्ध सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों पर कुल 700 मेगावाट रूफटाप सोलर पावर प्लाण्टों की स्थापना ।
- ◆ जनपद हापुड़ में 1000 करोड़ रुपये से 765 के.वी.ए. विद्युत उपकेन्द्र को पी.पी.पी. के आधार पर उच्चीकृत । नहतोर (बिजनौर), माट (मथुरा), बांदा एवं आगरा दक्षिण (आगरा) में प्रत्येक 400 के0वी0ए0 के उपकेन्द्रों को 1217 करोड़ रुपये से ऊर्जीकृत ।
- ◆ चन्दौसी (सम्भल), रनिया (कानपुर देहात), छाता (मथुरा), मोरटी (गाजियाबाद), अमरोहा, जहांगीराबाद (बुलन्दशहर) तथा हापुड़ में कुल 597 करोड़ रुपये से सभी 220 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्री ऊर्जीकृत ।
- ◆ बिचपुरी (आगरा), दनकौर (गौतमबुद्धनगर), गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़), सलोन (अमेठी), महमूदाबाद (सीतापुर), गभाना (अलीगढ़), ग्वालियर रोड (आगरा), बिन्दवल जयराजपुर (आजमगढ़), बण्डा (शाहजहांपुर), मवानारोड (मेरठ), हमीरपुर, पयागपुर (बहराइच), नवाबगंज (गोण्डा), जरी (इलाहाबाद), जलालाबाद (शामली), लालपुर (रामपुर) तथा भोपा (मुजफरनगर) में 132-132 के0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र बनाने पर 538 करोड़ रुपये व्यय ।



किसानों की सरकार



- ◆ प्रदेश के लगभग 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों जिनके द्वारा दिनांक 31.मार्च 2016 तक फसली ऋण प्राप्त किया गया है उनके ऋण खाते में दिनांक 31 मार्च 2017 तक बकाये से रू0 एक लाख की धनराशि तक की सीमा का ऋण मोचन प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए 36000 करोड़ रू0 का बजट प्राविधान।
- ◆ वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का रोडमैप तैयार।
- ◆ कुल 233.25 लाख कृषकों के सापेक्ष अब तक 102.39 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण।
- ◆ बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 2367 तालाबों पर कार्य पूर्ण।
- ◆ खरीफ 2017 में 8.02 लाख कु0 प्रमाणित बीज वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 8.25 लाख कु0 की उपलब्धता तथा 8.08 लाख कु0 का वितरण। 3.01 लाख कु0 संकर बीज वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 3.04 लाख कु0 की उपलब्धता तथा 2.65 लाख कु0 का वितरण। रबी 2017-18 में 44.62 लाख कु0 बीज वितरण का लक्ष्य। जून 2017 तक प्रथम चरण में 423 करोड़ रुपये से 3701 कि0मी0 मार्गों को गड्ढा मुक्त किया गया।
- ◆ आलू उत्पादकों का परिवहन भाड़ा अनुदान दोगुना किया गया। आलू उत्पादकों को 50 रू0 प्रति कुन्तल अथवा परिवहन भाड़े के 25 प्रतिशत में जो भी कम होगा, अनुदान के रूप में दिया जायेगा।
- ◆ सरकार ने किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को त्वरित गति से 25,386.87 करोड़ के सापेक्ष 23,843.76 करोड़ का भुगतान चीनी मिलों से कराया गया है।
- ◆ गन्ना आपूर्ति करने से वंचित किसानों को "गन्ना विभाग किसान के द्वार तुरन्त सदस्यता पहली बार" के संकल्प के साथ 25,271 किसानों को घर बैठे गन्ना समिति का सदस्य बनाया गया है।
- ◆ 13 मार्च, 2018 तक प्रदेश के सभी 33 लाख आपूर्तिकर्ता गन्ना किसानों को किसान कॉल सेंटर एवं भारत सरकार के कृषि मंत्रालय एम-किसान पोर्टल से जोड़ा जायेगा।
- ◆ सहकारी चीनी मिल रमाला (बागपत) की क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 5000 टीसीडी किये जाने एवं 25 मेगावाट कोजेन प्लाण्ट लगाने की स्वीकृत दी गयी है।
- ◆ यह परियोजना नवम्बर 2018 में पूर्ण होना सम्भावित है।
- ◆ निगम क्षेत्र की "मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल (मेरठ)" के क्षमता विस्तारीकरण एवं कोजेन की स्थापना हेतु 152 करोड़ रुपये की लागत से कराया गया है।
- ◆ इससे आगामी घेराई सत्र में मिल का विस्तारित क्षमता के साथ समय से संचालन सुनिश्चित किये जा सकेंगे।
- ◆ निगम क्षेत्र की 02 बन्द चीनी मिलों "पिपराईच (गोरखपुर) एवं मुण्डेरवा (बस्ती) "में 3500 टी.सी. डी. क्षमता की नयी चीनी मिले, 15 मेगावाट का कोजेन तथा 30 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का डिस्टलरी संयंत्र लगाकर पुर्नसंचालित करने का निर्णय लिया गया है।



- ◆ वित्तीय वर्ष 2017-18 में पिपराइच इकाई हेतु 273.75 करोड़ रुपये तथा मुण्डेरवा इकाई के लिए 270 रुपये करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। ये परियोजनाएं नवम्बर 2018 में पूर्ण होना सम्भावित है।
- ◆ शरदकालीन गन्ना बुवाई हेतु 1,65,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।
- ◆ विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-121-3203 पर गन्ना किसान घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसका निवारण तत्काल किया जायेगा।
- ◆ 80 लाख कुंटल उन्नतिशील प्रजातियों का उच्च गुणवत्तायुक्त गन्ना बीज गन्ना कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- ◆ यूपीडास्प द्वारा संचालित क्राप डाइवर्सिफिकेशन योजनान्तर्गत 6 माह में 33228 हे. क्षेत्रफल का डाइवर्सिफिकेशन पूर्ण।
- ◆ 1061 नयी बोरिंग के माध्यम से 4244 क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास।
- ◆ जिप्सम के प्रयोग से 10121 हेक्टेयर भूमि को खेती योग्य बनाया गया।
- ◆ यूरिया खाद का पारदर्शी वितरण।
- ◆ बीहड़ पायलेट परियोजना के अन्तर्गत चयनित वाटर शेड्स में आच्छादित 99 ग्रामों के प्रक्षेत्र विकास के लगभग 94 प्रतिशत कार्य।
- ◆ ऊसर भूमि के उपचार के साथ 61 जल निकास नालों का पुनरुद्धार कराकर 45000 हेक्टेयर भूमि में जलभराव की समस्या का निराकरण।
- ◆ प्रदेश के समस्त 34 सीबीएस कम्प्यूटराइज्ड जिला सहकारी बैंकों में रूपे के0सी0सी0 कार्ड प्रणाली लागू।
- ◆ प्रदेश में अब तक 14.06 लाख रूपे के0सी0सी0 कार्डों का वितरण।
- ◆ खरीफ हेतु यूरिया का लक्ष्य 963441 के सापेक्ष 750634 मैट्रिक टन एवं फास्फेटिक का लक्ष्य 253610 के सापेक्ष 175482 मैट्रिक टन का वितरण।
- ◆ मूल्य समर्थन योजना (गेहूँ खरीद) के तहत पीसीएफ द्वारा 17.69 लाख मै0 टन एवं पी0सी0यू0 द्वारा 1.56 लाख मै0 टन की कुल खरीद कृषकों को शत प्रतिशत भुगतान।



चिकित्सा : सबके स्वास्थ्य की चिन्ता



- ◆ प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों से भारत सरकार द्वारा पूर्वान्वल की जनता को एम्स के रूप में एक बड़ी भेंट। जनपद गोरखपुर में एम्स की स्थापना के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के मध्य दिनांक 13 जुलाई, 2017 को एम0ओ0यू0 निष्पादित। इससे पूर्वान्वल में जापानी इन्सेफिलाइटिस एवं एक्यूट इन्सेफिलाइटिस से निजात पाने में सहायता मिलेगी।
- ◆ डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में एम0बी0बी0एस0 की 150 सीटों की मान्यता एम0सी0आई0 के द्वारा प्रदान की गयी है और वर्तमान शैक्षणिक सत्र में उन सीटों पर काउंसिलिंग के माध्यम से छात्रों को प्रवेश।
- ◆ वर्ष 2017 में एम0सी0आई0 नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के विभिन्न राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालय में 133 पी0जी0 सीटों की अनुमति।
- ◆ नीट यू0जी0 2017 के आधार पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2017-18 में राजकीय मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 1673 सीटें तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 2550 सीटों पर आवंटन/प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पन्न।
- ◆ प्रदेश में प्रथम बार ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया 42000 अभ्यर्थियों द्वारा आनलाइन पंजीकरण कराया गया।
- ◆ शैक्षणिक सत्र 2017-18 में के0जी0एम0यू0 की बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सभी 51 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कर ली गयी है, जबकि निजी क्षेत्र के डेंटल कालेजों में वर्तमान में 2200 सीटों के सापेक्ष 1548 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण।



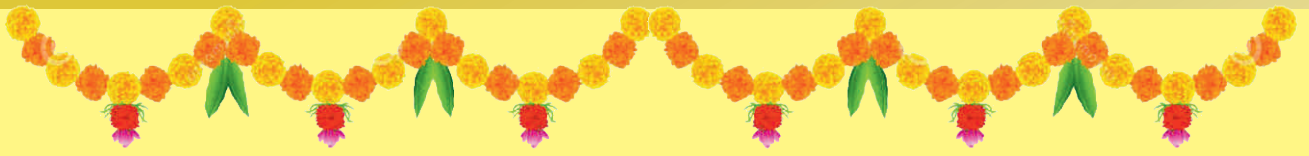
- ◆ पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान नोएडा में चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 04 अगस्त 2017 को मॉड्यूलर ओटी, नियोनेटल आईसीयू, आईसीयू काम्प्लेक्स तथा डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन, जो प्रदेश सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।
- ◆ ए.ई.एस./जे.ई. प्रभावित 38 जनपदों में विशेष कैम्प लगाकर 92 लाख बच्चों का प्रतिरोधक टीकाकरण।
- ◆ मिशन इन्द्रधनुष के अन्तर्गत 37 जनपदों के टीकाकरण से छूटे हुए 26.48 लाख बच्चों का टीकाकरण।
- ◆ सस्ती एवं गुणवत्तायुक्त औषधि उपलब्ध कराने के लिए एक हजार जन औषधि केन्द्र स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- ◆ पं० दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों तथा उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने का निर्णय। अब तक पांच लाख कर्मचारियों का पंजीकरण।
- ◆ गम्भीर रोगियों को शीघ्रता से अस्पतालों तक पहुंचाने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 150 "एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस" सेवा शुरू की गई। चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गयी।
- ◆ रिक्त 7348 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। 1000 चिकित्सकों की वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ।
- ◆ जे.ई./ए.ई.एस. रोग पर नियंत्रण हेतु गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल में 'दरवाजा खटखटाओ दिमागी बुखार घर-घर से भगाओ' जागरूकता कार्यक्रम।
- ◆ निर्माणाधीन 02 नये राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों गोरखपुर एवं अलीगढ़ के निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से अलीगढ़ कालेज के निर्माण हेतु ₹0 388.50 लाख की स्वीकृतियों निर्गत तथा रा० गोरखपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्राचार्य की तैनाती।
- ◆ प्रदेश के सभी 06 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों को सीसीएच के मानक के अनुसार सुदृढ़ किये जाने हेतु आवश्यक निर्माण कार्य, उपकरण फर्नीचर तथा बुक्स आदि हेतु कुल ₹0 1123.64 लाख की कार्ययोजना का आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त।
- ◆ सभी जनपदों में योग वेलनेस सेन्टर की स्थापना के अन्तर्गत 40 जनपदों में 42 सेन्टर की स्थापना की जा रही है।
- ◆ लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, बरेली, बस्ती एवं कुशीनगर में 50 शैय्या युक्त एकीकृत चिकित्सालय के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्थाओं का चयन। 28 चिकित्सालयों में ई-हास्पिटल का कार्य प्रगति पर। डा० राम मनोहर लोहिया एवं डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में ई-हास्पिटल परियोजना क्रियान्वित।
- ◆ 40 जनपदों में 50 से अधिक प्रसव भार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पी.पी.पी. मोड पर अल्ट्रासाउण्ड प्रारम्भ।
- ◆ राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत 34 नये नागरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सापेक्ष 10 केन्द्र का संचालन प्रारम्भ।

ग्राम्य विकास : ऐसा होगा मेरा गांव



- ◆ प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के अन्तर्गत 6 माह में 9.76 लाख लाभार्थियों को पंजीकृत कर 8.00 लाख से अधिक आवासों को स्वीकृत कर लाभार्थियों के खाते में सीधे 3000 करोड़ रू0 से अधिक की धनराशि अवमुक्त। प्रधानमंत्री आवास योजना— ग्रामीण के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को रू0 175 प्रति दिवस की दर से 90 दिन का अकुशल श्रमिक रोजगार देने की व्यवस्था।
- ◆ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में कार्यों की पारदर्शिता को बढ़ाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आधार बेस्ड पेमेण्ट सिस्टम लागू।
- ◆ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 13000 स्वयं सहायता समूहों का गठन व उन्हें रिवाल्विंग फण्ड एवं 7000 स्वयं सहायता समूहों को निवेश निधि उपलब्ध करायी गयी।
- ◆ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 250 मार्गों को 15 जून तक गड़ढामुक्त किया गया।
- ◆ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 37 मार्गों का निर्माण। लगभग रू0 2500 करोड़ की नई परियोजनाएं तैयार की गईं।
- ◆ आईसीडीएस, मनरेगा एवं पंचायतराज की कनवर्जेन्स के अन्तर्गत लगभग 10,000 **आँगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण** वर्ष 2017—18 में लक्षित।
विधायक निधि, सांसद निधि एवं पूर्व विधायक निधि तथा अन्य योजना के अन्तर्गत 2531 सम्पर्क मार्गों का निर्माण।
- ◆ विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 908 भवनों का निर्माण।
- ◆ अब तक 30प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कुल 3225 आन्तरिक सी0आर0पी0 का चयन किया गया। 2226 आन्तरिक सी0आर0पी0 को प्रशिक्षण। गरीब ग्रामीण महिलाओं को कुल 11998 स्वयं सहायता समूहों का गठन पूर्ण। कुल 13597 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड से आवश्यक सहायता प्रदत्त। अब तक कुल 6903 स्वयं सहायता समूहों को निवेश निधि उपलब्ध।
- ◆ मिशन (यू0पी0एस0आर0एल0एम0) द्वारा तेलंगाणा, आन्ध्रप्रदेश एवं बिहार राज्यों के साथ सी0आर0पी0 (कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन) की सेवायें उपलब्ध कराने का अनुबन्ध। इससे स्वयं सहायता समूहों के गठन हेतु जनसामान्य को अधिक से अधिक लाभ।





सिंचाई : मिलेगा हर खेत को पानी



- ◆ 1425 फसली खरीफ में 5743 कि०मी० में सिल्ट सफाई। खरीफ फसल में नहरें चलाकर 8800 टेलें फीड कराई गई।
- ◆ ग्रीष्म ऋतु में जानवरों/पक्षियों के पीने के पानी के लिए नहर/नलकूप चलाकर 32884 अदद तालाब भरे गये।
- ◆ रामगंगा बांध कालागढ़ में टनल टी-1 एवं टी-2 में गत वर्षों से खराब वाटर सप्लाई वाल्व एवं सिलेण्ड्रोक्ल गेट की मरम्मत। बांध के 348.540 मीटर लेवल तक पानी भरा गया।
- ◆ 523 तटबंधों एवं 1300 कटाव निरोधक कार्यों का अनुरक्षण। बलिया एवं सिद्धार्थनगर के क्षतिग्रस्त तटबंधों का निर्माण। 14 अदद बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण। 541.315 कि०मी० ड्रेनों की सफाई का कार्य पूर्ण।
- ◆ पंजीकृत दागी फर्मों एवं आपराधिक प्रवृत्ति के ठेकेदारों का पंजीयन समाप्त। अच्छी, साफ-सुथरी छवि की संस्थाओं को मौका देने तथा विभाग में कय/आपूर्ति व निर्माण आदि कार्यों में ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया का अपना रोल समिचित करने की व्यवस्था



ई-गवर्नेंस: डिजिटल उत्तर प्रदेश



- ◆ 1 अक्टूबर, 2017 से उत्तर प्रदेश में लागू हो रही है ई-ऑफिस व्यवस्था ।
- ◆ 31 अक्टूबर, 2017 तक पूरे सचिवालय के 95 विभागों के 455 अनुभागों में पूरी तरह से लागू कर दिया जायेगा ।
- ◆ 1 जनवरी, 2018 से जिला मुख्यालयों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जायेगा ।
- ◆ सचिवालय के 4000 कर्मियों को इस प्रणाली के मद्देनजर आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।
- ◆ उत्तर प्रदेश में सभी शासकीय विभागों में 1 सितम्बर से ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की जा चुकी है । 40,000 बिडर्स के डिजिटल सिग्नेचर्स पंजीकृत ।
- ◆ रू 1,000 करोड़ के स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना
- ◆ मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में लगभग 15000 रोजगार सम्भावनाओं युक्त आईटी पार्क्स की स्थापना प्रगति पर है ।
- ◆ स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा । उद्यमिता के प्रोत्साहन के लिए 6 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत । 13 अन्य इन्क्यूबेटर्स के कार्य प्रगति पर हैं ।
- ◆ देश के सबसे बड़े इन्क्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में शीघ्र ।



नगर विकास : शहरों को लगे पंख



- ◆ स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों को 02 अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित। इस हेतु 07 सितम्बर 2017 तक कुल 130031 निजी शौचालयों, 11187 सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण नगरीय क्षेत्रों में।
- ◆ अयोध्या एवं मथुरा-वृन्दावन को नगर निगम बनाया गया। भारत सरकार ने इलाहाबाद, अलीगढ़ एवं झाँसी नगरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया। लखनऊ, आगरा, कानपुर एवं वाराणसी चारों को स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के तहत कुल 881.60 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी।
- ◆ नगरों में स्ट्रीट लाईट पर होने वाली ऊर्जा को बचाने के लिए परम्परागत मार्ग प्रकाश बिन्दुओं को एल0ई0डी0 में परिवर्तित करने हेतु भारत सरकार की संस्था ईईएसएस के साथ समझौता।
- ◆ 31 शहरों में लगभग 56255 मकानों को निजी जल कनेक्शन प्रदान किये गये जिससे लगभग 2,81,300 जाना लाभान्वित हुये। 13 शहरों में लगभग 55,000 मकानों को सीवरेज कनेक्शन प्रदान किये गये जिससे 2,75,000 लाभ लाभान्वित हुये।
- ◆ लखनऊ मेट्रो के अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण कर ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक निर्मित प्राथमिक सेक्शन पर 5 सितम्बर को मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। द्वितीय चरण का कार्य मार्च 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य।





- ◆ कानपुर, झाँसी, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर और मेरठ में मेट्रो या रैपिड अर्बन ट्रांसपोर्ट सुविधा की योजना ।
- ◆ अमृत योजना के अन्तर्गत 11 शहरों की 477 करोड़ रुपये की 11 पेयजल एवं सीवरेज योजनायें स्वीकृत ।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- ◆ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 05 लाख आवास बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित ।
- ◆ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष अब तक राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा 348 परियोजनाओं में 108830 आवास की डीपीआर भारत सरकार से स्वीकृत ।



उम्मीदों की रफ्तार : परिवहन



- ◆ उ0प्र0 एवं राजस्थान के बीच सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन समझौता। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एवं उत्तराखण्ड राज्यों के साथ शीघ्र परिवहन समझौता।
- ◆ रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा। महिला यात्रियों की सुविधा के लिए पिंक बसों का संचालन। शीघ्र ही केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को 50 पिंक बसें उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित।
- ◆ प्रदेश में ओवरलॉडिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित। सम्भागीय एवं सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों को दलाल मुक्त किया गया। ई-चालान व्यवस्था का क्रियान्वयन।



- ◆ प्रदेश के प्रमुख बस स्टेशनों पर वाटर ए.टी.एम. की सुविधा। जिला मुख्यालय के बस स्टेशनों पर फ्री वाई-फाई की सुविधा।
- ◆ मण्डल मुख्यालयों में ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की परिकल्पना। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने संबंधी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने तथा वाहनों के फिटनेस में मानवीय हस्तक्षेप कम करने लिए ड्राइविंग सिमुलेटर एवं आटोमैटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक स्थापित किये जाने की परिकल्पना।
- ◆ जनपद लखनऊ में वाहन इंस्पेक्शन एवं सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। जनपद रायबरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च सेंटर की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
- ◆ सभी ग्रामों को निजी बस सेवा के द्वारा चरणबद्ध तरीके से शहर से जोड़ा जायेगा। परिवहन निगम के कुल 73 डिपो में आटोमैटिक फ्यूल सिस्टम लागू किया जायेगा।
- ◆ कानपुर नगर व बरेली में आटोमैटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का लोकार्पण।
- ◆ स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्धता हेतु वाराणसी, गाजियाबाद, इलाहाबाद तथा मेरठ में सारथी हाल का लोकार्पण। कक्षा-09 से 12 तक के विद्यार्थियों के कोर्स में यातायात शिक्षा को अनिवार्य बनाना।



व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास



- ◆ कौशल विकास मिशन के तहत सरकार गठन के प्रथम वर्ष में 3 लाख 11 हजार युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 20 लाख युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य तथा रोजगार प्रदान कराने में मदद।
- ◆ विश्व युवा कौशल दिवस (दिनांक 15 जुलाई 2017) पर 1100 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित। निजी क्षेत्र की कम्पनी राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, भीलवाड़ा ग्रुप के साथ अगले 04 वर्षों में 26000 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार देने संबंधी एमओयू हस्ताक्षरित।
- ◆ आई.टी.आई. में 4000 प्रशिक्षण सीटों की वृद्धि।
- ◆ रोजगार मेले का आयोजन कर गोरखपुर व बस्ती मण्डल के 4772 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अन्तर्गत 22 परियोजनायें स्वीकृत।

विभागीय परियोजनाओं का लोकार्पण
तथा सेवायोजित प्रशिक्षण



- ◆ लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार योजना में डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण ।
- ◆ डा. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज का संचालन ।
- ◆ डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के नोएडा कैम्पस में इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का संचालन ।
- ◆ सेन्टर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये जाने की योजना प्रगति पर । लगभग 80000 युवाओं को प्रशिक्षण ।
- ◆ डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा तीन परियोजनायें क्रमशः विश्वेसरैया शोध सहायता परियोजना, सी.वी. रमन असिस्टेंट्सशिप प्रोग्राम तथा होमी भाभा पी.एच.डी. असिस्टेंट्सशिप प्रोग्राम प्रारम्भ ।
- ◆ छात्र-छात्राओं को सेवायोजित कराने हेतु लखनऊ, नोयडा एवं गोरखपुर में 'मेगा जॉब फेयर' का आयोजन ।

काव्यण, काशल प्रदशना का उद्घाटन,
गार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण

मयी उपस्थिति -
गौर्या

श्री श शर्मा

अध्यक्ष, मंत्री,



- ◆ लखनऊ में 30 एकड़ भू-क्षेत्र में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना। 500 प्रशिक्षार्थियों की क्षमता वाला कौशल विकास केन्द्र-1 कार्यरत। 1000 प्रशिक्षार्थियों की क्षमता वाला कौशल विकास केन्द्र-2 निर्माणाधीन।
- ◆ 16 राजकीय पालीटेक्निकों एवं 15 छात्रावासों का निर्माण पूर्ण कराकर हस्तान्तरित किया गया। 96 चिन्हित राजकीय पालीटेक्निकों में निःशुल्क वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु रिलायंस जियो के साथ एम.ओ.यू. एवं 02 राजकीय पालीटेक्निकों में निःशुल्क वाई-फाई सुविधा का कार्य पूर्ण। 19 राजकीय पालीटेक्निकों में वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना।
- ◆ संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद मुख्यालय लखनऊ में 10 प्रमुख जनपदों के राजकीय पालीटेक्निकों में प्लेसमेंट सेल की स्थापना।

श्रम एवं सेवायोजन

- ◆ बाल श्रम मुक्ति के लिए “नया सवेरा योजना” क्रियान्वित।
- ◆ बन्धुआ श्रमिकों को तात्कालिक सहायता के लिए सभी जनपदों में 10 लाख रुपये का कार्पस फण्ड।
- ◆ 269 रोजगार मेलों का आयोजन कर 22492 बेरोजगार लाभार्थी रोजगार के लिए चयनित। 993 कैरियर काउंसिलिंग शिविरों में 88024 लाभार्थियों ने प्रतिभाग किया।
- ◆ कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कार्यरत एलोपैथिक/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सकों की अधिवर्षता 62 वर्ष की गयी। उ0प्र0 इम्प्लाइज स्टेट इन्श्योरेंस मेडिकल सर्विसेज सोसायटी का गठन।
- ◆ निर्माण श्रमिकों का पंजीयन शुल्क 50 रुपये से घटाकर 20 रुपये तथा वार्षिक अंशदान 50 रुपये से घटाकर 20 रुपये किया गया।
- ◆ संत रविदास शिक्षा सहायता योजनान्तर्गत अब तक 4189 छात्रों को छात्रवृत्ति।



अपना गाँव, अपना राज



गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत 25 जनपदों के विन्हित 1627 ग्रामों को खुले में शौच मुक्त करते हुए 3,98,828 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण।

प्रदेश के कुल 98,614 ग्रामों में से 9765 ग्राम खुले में शौच मुक्त (ओ.डी. एफ.) घोषित। वर्ष 2017-18 में अगस्त माह तक लगभग 9,17,049 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण।

2 अक्टूबर 2018 तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य।

दिसम्बर 2017 तक 30 जनपदों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य।

गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर और शामली जनपदों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मई, 2017 से अब तक 58679 हैण्डपम्पों की रिबोर/मरम्मत का कार्य।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को रुपये 4643 करोड़ अवमुक्त।







वाणिज्य कर

- ◆ 01 जुलाई-17 से Goods and Services Tax (GST) लागू।
- ◆ उत्तर प्रदेश पूरे भारत में GST व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वाला राज्य बना। प्रदेश सरकार की पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त कार्यप्रणाली की वजह से यह सम्भव हुआ।
- ◆ GST की वृद्धि दर 33.67 प्रतिशत रही जो एक रिकार्ड है।
- ◆ GST के सुचारु संचालन हेतु IT Infrastructure के निर्माण संबंधी कार्यवाही पूर्ण।
- ◆ जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पूरे देश में कहीं से भी माल अथवा सेवा लिए जाने पर आई0टी0सी0 उपलब्ध, जो वैट में केवल अपने राज्य में माल क्रय पर उपलब्ध थी।
- ◆ वैट व्यवस्था के अन्तर्गत विभाग में 775149 पंजीकृत व्यापारियों अर्थात् 89.2 प्रतिशत व्यापारियों को GST व्यवस्था में माइग्रेशन कराने का कार्य पूर्ण। इनमें से 531242 अर्थात् 68.53 प्रतिशत व्यापारी जी0एस0टी0 में इन्रोल्ड।
- ◆ GST के क्रियान्वयन हेतु GSTN के डाटा सेन्टर तथा स्टेट सेन्टर लखनऊ के मध्य कनेक्टिविटी का कार्य पूर्ण।
- ◆ पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू।
- ◆ वैट की भाँति जी0एस0टी0के अन्तर्गत ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू।

भूतत्व एवं खनिकर्म

- ◆ बालू/मोरम की आपूर्ति सुलभ कराने हेतु प्रदेश के 61 जनपदों में 381 क्षेत्रों पर 06 माह के लिए

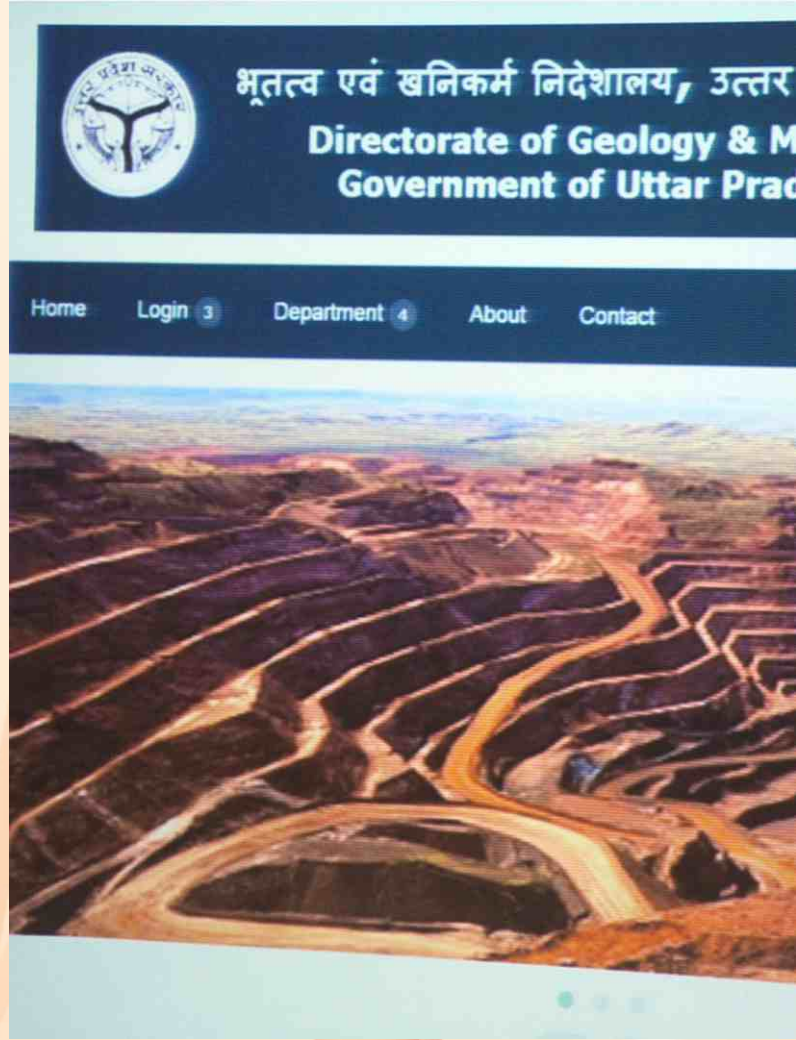
ई-टेण्डर के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ 43 जनपदों में कुल 160 क्षेत्रों पर माइनिंग परमिट हेतु लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी। इन क्षेत्रों पर जैसे-जैसे पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे हैं, वैसे-वैसे खनन कार्य प्रारम्भ हो रहा है।

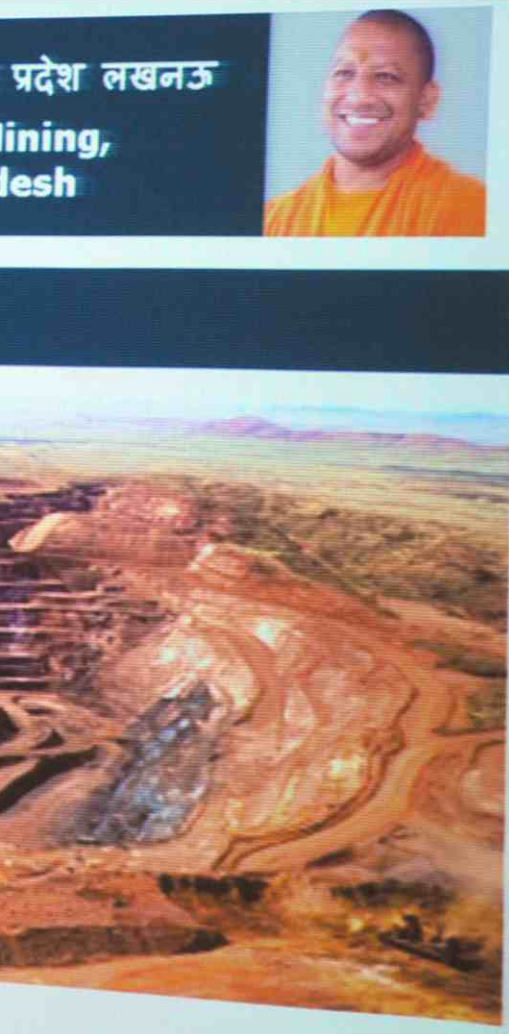
- ◆ अवैध खनन पर अंकुश लगाने तथा अवैध खनन जुमाने की धनराशि रुपये 25000 से बढ़ाकर न्यूनतम 02 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तथा अधिकतम 05 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की गयी। पूर्व में नियमावली में खनन पट्टों के नवीनीकरण की निहित व्यवस्था, जिससे एक ही व्यक्ति का एकाधिकार बना रहता था, को नियमावली के 42वें संशोधन दिनांक 18.05.2017 द्वारा विलोपित / समाप्त किया गया।

- ◆ खनिजों के अवैध परिवहन की सम्भावना पर रोक लगाने हेतु ई-ट्रांजिट पास (E-TP) जारी करने के लिए विभागीय पोर्टल लांच किया। अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु ई-एम0एम0-11 की व्यवस्था लागू।
- ◆ खनिजों के अवैध खनन को सेटेलाइट के माध्यम से ट्रैक करने हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित माइनिंग सर्विलांस सिस्टम (MSS) को उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
- ◆ दीर्घकालीन पट्टों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु नियमावली प्रख्यापित।
- ◆ प्रदेश के सोनभद्र जनपद में दो खनन क्षेत्रों का उपग्रहीय आंकड़ों के माध्यम से चिन्हांकन तथा सजरा स्तर पर डिजिटल डाटाबेस तैयार किया गया।

आबकारी

- ◆ आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए कुल आबकारी राजस्व का लक्ष्य रुपये 20595 करोड़ है। अगस्त, 2017 तक विभाग द्वारा रुपये 6425.90 करोड़ अर्जित किया जा चुका है।





- ◆ शीरा नीति वर्ष 2016–17 का दिनांक 13.07.2017 को निर्धारण कर दिया गया है।
- ◆ आबकारी विभाग द्वारा दिनांक 01 मई, 2017 को 121 सर्किल/सेक्टर चिन्हित किये गये। अवैध मद्य निष्कर्षण एवं मदिरा की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण लगाया गया।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन

- ◆ प्रदेश के सभी उप निबन्धक कार्यालयों से संबंधित नियत गत 10 वर्षों की मूल्यांकन सूची आनलाईन विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध।
- ◆ भारमुक्त प्रमाण पत्र की आनलाईन उपलब्धता सुनिश्चित की गयी। नियमित निबन्धित अभिलेखों की प्रतिलिपि को आनलाईन उपलब्ध कराने की व्यवस्था स्थापित।
- ◆ परम्परागत कोर्ट फीस (टिकट एवं स्टाम्पों) के साथ साथ स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से ई-कोर्ट फीस की वैकल्पिक व्यवस्था लागू।



जन-जन का कल्याण



- ♦ पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति के कुल 93 विद्यालयों, 35 विद्यालयों की CBSE Board से सम्बद्धता। शेष की कार्यवाही प्रगति पर। 30 विद्यालयों में हाईटेक शिक्षा हेतु स्मार्ट क्लास रूम स्थापित।
- ♦ माता-पिता एवं भरण-पोषण अधिनियम के अन्तर्गत पी.पी.पी. मॉडल पर स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा 75 जनपदों में वृद्धाश्रम संचालित।

महिला कल्याण

- ♦ प्रदेश सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण अनिवार्य किया गया। विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्णतया ऑनलाइन की गयी।
- ♦ लैंगिक असमानता के प्रति जागरूकता लाने के लिए “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के क्रियान्वयन हेतु सेल की स्थापना करने का निर्णय।



- ♦ राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन में स्टेट रिसोर्स सेन्टर फॉर वुमेन एण्ड चाइल्ड (S.R.C.W.C) को सेन्टर ऑफ़ एकसीलेंस के रूप में स्थापित किया गया है। पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला की पेंशन योजना पर प्रदेश सरकार ने पात्रता हेतु 60 वर्ष की उम्र सीमा को समाप्त कर निराश्रित महिलाओं को विशेष राहत प्रदान की।
- ♦ 181 वूमेन हेल्पलाइन स्कीम में कॉल सेन्टर की क्षमता 06 सीटर से बढ़ाकर 30 सीटर की गई जिससे पीड़ित महिलाओं को सहायता के कॉल करना आसान हुआ है। 181 महिला हेल्पलाइन 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध करायी गयी है।
- ♦ महिलाओं की सहायता और विषम परिस्थितियों से ग्रस्त महिला को रेस्क्यू करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 जून 2017 को 64 रेस्क्यू वैन को हरी झंडी दिखाकर सेवा के लिए रवाना किया।
- ♦ पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु 'आशा ज्योति केन्द्रों' की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों पर एक ही छत के नीचे पीड़िता की एफ.आई.आर. लिखने के अतिरिक्त उसे परामर्श, मेडिकल चेकअप, कौशल विकास प्रशिक्षण दिए जाने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

युवा कल्याण

- ♦ 2474 युवक एवं महिला मंगलदलों के गठन का कार्य पूर्ण मंगलदलों का गठन अब राजस्वग्राम स्तर पर मंगलदलों को "सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860" के अधीन पंजीकरण की बाध्यता से मुक्त।
- ♦ 3589 पी0आर0डी0 जवानों को आंशिक ड्यूटी पर लगा कर रोजगार।
- ♦ ग्रामीण स्तर पर खेलो इण्डिया योजना में 26 स्थानों पर खेल अवस्थापना सुविधाओं के सृजन की कार्यवाही। समस्त महिला थानों में 06-06 महिला पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों की ड्यूटी लगाये जाने का निर्णय।
- ♦ विवेकानन्द यूथ एवार्ड योजना पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय।
- ♦ प्रत्येक जिले में एथलेटिक्स, वालीबाल, कुश्ती, भारोत्तोलन एवं कबड्डी विधा में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु 40,000 रु. की धनराशि आवंटित।

- ◆ प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान हेतु भूमि आरक्षित। जहां पर खेल मैदान हेतु भूमि पूर्व से ही उपलब्ध खेल मैदान बनाने का निर्णय।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण

- ◆ विभाग का नाम विकलांग जन विकास विभाग से परिवर्तित कर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग किया गया। दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु हेल्पलाइन नम्बर (1800-180-1995) शुरू की गयी।
- ◆ दिव्यांगजनों को भरण-पोषण अनुदान के रूप में अनुमन्य 300 रुपये प्रतिमाह की पेंशन धनराशि बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह की गयी।



- ◆ दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज से संगठनों/व्यक्तियों/सरकार तंत्र इत्यादि के योगदान को विशेष पहचान देते हुए प्रतिवर्ष दी जाने वाली पुरस्कार राशि 5000 रुपये को बढ़ाकर 25000 रुपये की गयी। इस संबंध में बनी नयी पुरस्कार नियमावली के तहत दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को 30 वर्गीकृत श्रेणी में प्रतिवर्ष सम्मानित किया जायेगा।
- ◆ दिव्यांगजन को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की प्रदेश से बाहर जाने वाली साधारण श्रेणी की बसों के अन्तिम गन्तव्य स्थल तक निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य की गयी। पूर्व में यह सुविधा प्रदेश के भीतर ही अनुमन्य थी।

- ◆ शल्य चिकित्सा अनुदान की धनराशि 8000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये की गयी।
- ◆ शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में देय पुरस्कार की धनराशि 20,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपये प्रति दम्पति की गयी।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

- ◆ पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 01 जुलाई, 2017 से छात्रों से ऑनलाइन आवेदन भराये जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके सापेक्ष अब तक 621188 छात्र/छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जा चुके हैं।
- ◆ दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत 01 जुलाई 2017 से छात्रों से ऑनलाइन आवेदन भराये जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके सापेक्ष अब तक 1053181 छात्र/छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जा चुके हैं।
- ◆ दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्राविधानित धनराशि 399.04 करोड़ रुपये को बढ़ाकर वर्तमान वित्तीय वर्ष में 510.04 करोड़ रुपये की गयी है।
- ◆ वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार दिलाये जाने में सहायक ओ-लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के साथ-साथ सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में ओ-लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु 5333 लाभार्थियों को प्रशिक्षित कराये जाने तथा सी0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु 8570 लाभार्थियों को प्रशिक्षित कराये जाने का लक्ष्य है।





औद्योगिक विकास : प्रदेश की आकांक्षा



- ◆ प्रदेश में उद्योग की स्थापना एवं पूँजी निवेश के प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 अधिसूचित ।
- ◆ उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 में दिये गये वित्तीय प्रोत्साहनों के कारण उद्योग की स्थापना हेतु उचित माहौल बना ।
- ◆ औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए ईज आफ डूइंग बिजनेस परियोजना के अन्तर्गत अधिकांश कार्यवाही पूर्ण ।
- ◆ अभी तक औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का आडिट केवल स्थानीय निधि संगठन द्वारा ही किया जाता था । औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा सहित सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का आडिट सी.ए.जी. द्वारा कराने के आदेश निर्गत ।

- ◆ उद्योगों की स्थापना के लिए यूपीएसआईडीसी द्वारा भूमि/भूखण्ड अधिग्रहीत कर विकसित किये जाते हैं। औद्योगिक भूखण्डों की उपलब्धता/उनकी लोकेशन/भूखण्ड का आकार आदि की जानकारी सुलभ कराने हेतु ई-अप्लीकेशन पर सम्पूर्ण विवरण जनसामान्य के लिए अपलोड।
- ◆ लखनऊ से गाजीपुर तक प्रस्तावित पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के विरुद्ध 61 प्रतिशत से अधिक भूमि का क्रय/अधिग्रहण पूर्ण।
- ◆ शासकीय विभागों में सामग्री व सेवाओं के क्रय के लिये भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नेट ई-मार्केटप्लेस, (GeM) अंगीकृत, जिसका शासनादेश वेबसाइट shasanadesh.up.nic.in पर उपलब्ध।
- ◆ सी0एफ0सी0 पैकेजिंग एण्ड स्टोरेज फॉर फूड एण्ड वेजिटेबिल परियोजना, लखनऊ में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को एक ही स्थान पर डिजाइन डेवलेपमेण्ट ट्रेनिंग, विपणन एवं पैकेजिंग आदि की सुविधा उपलब्ध।
- ◆ डिजाइन डेवलेपमेण्ट एण्ड ट्रेनिंग सेण्टर फॉर जरी इंडस्ट्री लखनऊ परियोजना पूर्ण। इस परियोजना में जरी कारीगरों को ट्रेनिंग सुविधा उपलब्ध जिससे अच्छी क्वालिटी, आधुनिक डिजाइन का माल तैयार हो सकेगा।



हर प्रतिभा को मिलेगा मौका : खेल विभाग



- ◆ केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु 592 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण। 410 अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की तैनाती। 280 खिलाड़ियों को आवासीय छात्रावास में प्रवेश दिया गया।
- ◆ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु 24 प्रदेशीय टीम को प्रशिक्षण। वर्ष 2017-18 में प्रशिक्षण मद में रू0 10.00 करोड़ का प्राविधान।
- ◆ पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के जन्मशताब्दी वर्ष के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 02-02 जिला स्तरीय जूनियर प्रतियोगिताओं एवं मण्डलीय मुख्यालयों पर 01-01 राज्य स्तरीय सीनियर प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- ◆ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। कुल 14 खिलाड़ी पुरस्कृत। पुरस्कृत खिलाड़ियों को रू0 3,11,000/-नकद धनराशि, प्रशस्ति पत्र एवं कांस्य प्रतिमा प्रदान की गयी।
- ◆ 12वें साउथ एशियन गेम्स-2016 में बुशु खेल में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को



रू0 3,00,000 /– एवं हैण्डबाल (टीम गेम्स) में स्वर्ण पदक विजेता 04 खिलाड़ियों को (उ0प्र0 के मूल निवासी) रू0 1,00,000 /– का नकद पुरस्कार ।

- ♦ आई0सी0सी0 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप–2017 में रजत पदक विजेता भारतीय टीम की उ0प्र0 की 02 महिला खिलाड़ियों को रू0 8.00 लाख–8.00 लाख नकद पुरस्कार। तुर्कीस ओपेन इन्टरनेशनल पैरा बैडमिन्टन चैम्पियनशिप एवं बीजिंग चाइना में आयोजित एशियन पैरा बैडमिन्टन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को रू0 10.00 लाख की नकद पुरस्कार ।



- ♦ जनपद गाजीपुर में नवीन स्टेडियम के निर्माणार्थ रू0 208.33 लाख स्वीकृत। जनपद बलिया में स्पोर्ट्स कालेज के निर्माणार्थ रू0 372.78 लाख स्वीकृत। “खेलो इण्डिया” के अन्तर्गत जनपद मेरठ में सिन्थेटिक हॉकी मैदान के निर्माण हेतु रू0 1.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। “खेलो इण्डिया” के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के लालपुर स्पोर्ट्स काम्पलेक्स में सिन्थेटिक रनिंग ट्रैक के निर्माण हेतु रू0 3.50 करोड़ स्वीकृत। जनपद गोरखपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्मित खेल अवस्थापनाओं के सुदृढीकरण हेतु रू0 300.00 लाख की बजट की व्यवस्था ।



आस्था से पर्यटन तक



- ◆ कुंभ मेला 2019 में विकास कार्य हेतु रू0 510 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास ।
- ◆ रू0 370.00 करोड़ की लागत से विश्व बैंक सहायित् प्रो-पूअर पर्यटन विकास परियोजना स्वीकृत । इसके अन्तर्गत आगरा एवं बृज क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है ।
- ◆ भारत सरकार के स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत रामायण सर्किट के अन्तर्गत श्रृंगवेरपुर एवं चित्रकूट के पर्यटन विकास हेतु भारत सरकार से कुल 69.45 करोड़ स्वीकृत ।
- ◆ भारत सरकार द्वारा बुद्धिस्ट सर्किट के अन्तर्गत कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती एवं वाराणसी के विकास हेतु रू0 100 करोड़ की धनराशि स्वीकृत ।
- ◆ प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत वाराणसी के समेकित पर्यटन विकास हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 20.40 करोड़ की धनराशि स्वीकृत । 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण ।
- ◆ प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत मथुरा वृन्दावन में टूरिस्ट फ़ैसिलीटेशन सेन्टर के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 935.76 लाख की स्वीकृति प्राप्त ।



- ◆ अयोध्या में सरयू नदी के घाटों का जीर्णोद्धार एवं नियमित आरती की व्यवस्था ।
- ◆ परम्परागत रामलीला का मंचन पुनः प्रारम्भ कराया गया ।
- ◆ मथुरा-वृन्दावन के पर्यटन विकास हेतु रू0 1493.09 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष प्राप्त धनराशि से कार्य पूर्ण ।
- ◆ स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत स्प्रिचुअल सर्किट-1 एवं सर्किट-2 तथा हेरिटेज सर्किट के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार की कार्यदायी संस्थाओं को भूमि उपलब्ध करायी गयी ।
- ◆ आगरा, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, इलाहाबाद एवं लखनऊ में पर्यटकों की सुविधा हेतु हेलीकाप्टर की सुविधा संचालित किये जाने की योजना ।
- ◆ कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु तीर्थ यात्रियों की अनुदान धनराशि 50 हजार रू0 से बढ़ाकर रू0 1 लाख की गयी ।
- ◆ तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए गाजियाबाद में लगभग रू0 93 करोड़ की लागत से कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का शिलान्यास ।



बनी रहे हरियाली



- ◆ प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले सहमति / प्राधिकार आवेदन पत्रों के त्वरित एवं पारदर्शिता पूर्ण निस्तारण के लिये आनलाइन कन्सेन्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू।
- ◆ पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य की सुरक्षा अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं (टी0एस0डी0एफ0), संरक्षित लैण्डफिल सुविधा (एस0एल0एफ0) समाकलित इलेक्ट्रानिक, पुनर्चक्रण एवं उपचार सुविधा (इन्टीग्रेटेड ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग एण्ड ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी) तथा सामूहिक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट उपचार एवं निस्तारण सुविधा (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट एण्ड डिस्पोजल फैसिलिटी) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता देने हेतु उद्यमियों से प्रस्ताव प्राप्त किये जाने की कार्यवाही।

वन एवं वन्यजीव

- ◆ वानिकी को People Friendly बनाने एवं Ease of doing business की दृष्टि से राज्य वन नीति 1998 का पुनरीक्षण किया जा रहा है।
- ◆ कृषि वानिकी प्रोत्साहन हेतु वृक्ष संरक्षण अधिनियम एवं अभिवहन नियमावली का सरलीकरण प्रचलित।
- ◆ मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना—इसके तहत खेतों की मेड़ पर रोपण प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना—इसके तहत सामुदायिक भूमि पर रोपण प्रस्तावित है।
- ◆ मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना— इसके तहत निजी खेतों में फल प्रजाति का रोपण प्रस्तावित है।
- ◆ प्रदेश में प्रथम बार बेसिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को पौध निःशुल्क उपलब्ध कराकर उनके माध्यम से इसका रोपण विद्यालय प्रांगणों में किया गया। अब तक 10.65 लाख पौध रोपित।





जुड़ेंगे जनता से



- ♦ पं० दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में उनके जीवन वृत्त एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर जनपद मुख्यालय एवं विकास खण्ड स्तर पर लगभग 925 प्रदर्शनियाँ आयोजित की गयी। पं० दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने हेतु 7000 सम्पूर्ण वांग्मय सेट का क्रय कराकर उनका वितरण प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थित विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज, राजकीय इण्टर कालेज एवं मण्डल एवं जिला मुख्यालयों पर स्थित पुस्तकालयों को वितरित कराया गया।
- ♦ प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु दो करोड़ ₹0 तक अनुदान कर प्राविधान।
- ♦ सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के युवाओं एवं आमजनों से सीधा संवाद स्थापित करने हेतु सभी विभागों द्वारा सोशल मीडिया प्रोफाइल/हैंडल स्थापना का निर्णय तथा इस हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाने का निर्णय। सोशल मीडिया पर जनता की अभिव्यक्ति के बेहतर एवं ससमय प्रतिक्रिया हेतु लोक भवन में सोशल मीडिया हब की स्थापना का निर्णय।
- ♦ उत्तर प्रदेश संदेश पत्रिका को पहली बार ग्राम पंचायतों तक डाक विभाग के माध्यम से प्रेषित किया गया।
- ♦ सरकार की नीतियों/योजनाओं को अच्छी गुणवत्ता की फिल्मों/टी.वी.सी. के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु पहली बार विख्यात मल्टीमीडिया एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया।



सपनों की उड़ान



- ◆ प्रदेश में नागरविमानन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए "उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017" प्रख्यापित।
- ◆ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत प्रथम चरण की बिडिंग में आगरा-जयपुर, कानपुर-दिल्ली, लखनऊ-ग्वालियर, कानपुर-वाराणसी एवं आगरा-दिल्ली नए एयर रूट चयनित। बरेली में सिविल इन्चलेव का निर्माण कार्य प्रारम्भ। जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए सर्वे का कार्य पूर्ण एवं भारत सरकार से सहमति प्राप्त।
- ◆ गोरखपुर एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल का नामकरण "महायोगी गोरखनाथ सिविल टर्मिनल" तथा आगरा एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल का नामकरण "पंडित दीन दयाल उपाध्याय सिविल टर्मिनल" करने हेतु संकल्प पारित।
- ◆ सिविल इन्चलेव के निर्माण हेतु भूमि क्रय करने के लिए इलाहाबाद की अवशेष 121.00 करोड़ रु0, आगरा की अवशेष 64.94 करोड़ रु0 तथा कानपुर नगर की अवशेष 31.31 करोड़ रु0 की धनराशि अवमुक्त।
- ◆ प्रमुख पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए आपस में जोड़े जाने हेतु पवन हंस लि0 के साथ एम0ओ0यू0।



पोषित हो अगली पीढ़ी



- ◆ कुपोषण की रोकथाम हेतु 'शबरी एक्शन प्लान'। विलेज हेल्थ न्युट्रिशन डे में दी जाने वाली सेवाओं की प्रभावी डिलेवरी के लिए 'मेगा कॉल सेन्टर'।
- ◆ मातृ-शिशु मृत्युदर व मातृ बाल कुपोषण में कमी लाने हुए 'कुपोषण मुक्त गांव' बनाने का निर्णय। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 5, 15 एवं 25 तारीख को क्रमशः बचपन दिवस, ममता दिवस एवं लाडली



दिवस का आयोजन। इसके अन्तर्गत लाभार्थियों का जन्मदिन, अन्नप्राशन एवं गोदभराई का कार्यक्रम जन सहायोग के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रदेश के 41 जनपदों के 91179 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अन्नप्राशन एवं गोदभराई का कार्यक्रम अब तक सम्पन्न।

- ◆ मनरेगा, पंचायतीराज एवं आई.सी.डी.एस. विभाग के कन्वर्जेंस के माध्यम से 9269 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण प्रगति पर।
- ◆ 51195 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को रियल टाइम मॉनीटरिंग हेतु स्मार्ट फोन का वितरण कर ऑनलाइन अनुश्रवण।





गुणवत्तापूर्ण हुआ पशुपालन



- ◆ प्रदेश में पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 80481 पशुओं को पशुधन बीमा से आच्छादन ।
- ◆ ग्राम पंचायत स्तर पर 2931 पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन । 53345 बांझपन समस्या से ग्रसित दुधारू पशुओं को समुचित चिकित्सा, बांझपन दूर ।
- ◆ खुरपका—मुंहपका रोग नियंत्रण हेतु किसानों / पशुपालकों के द्वार पर टीकाकरण करने की व्यवस्थाएं ।
- ◆ 2.03 करोड़ पशुओं को गला घोटू टीकाकरण से अच्छादित किया गया ।
- ◆ 57.73 लाख अतिरिक्त अण्डे का उत्पादन किया गया ।
- ◆ भूमिहीन कृषक मजदूरों को सूकर पालन में प्रशिक्षित कराकर 304 नर मादा सूकर शावक प्रजनन एवं रोजगार हेतु आवंटित ।
- ◆ बुंदेलखण्ड में अन्ना प्रथा उन्मूलन के लिए गुणवत्तायुक्त मादा संतति की प्राप्ति हेतु सेक्स सार्टेड सीमेन के व्यापक प्रयोग की कार्ययोजना ।



मत्स्य पालन अब आसान



- ◆ 3926.27 हे० जल क्षेत्र के ग्राम सभा तालाबों का पट्टा आवंटन कराते हुए 4321 परिवारों द्वारा मत्स्य पालन का।
- ◆ वर्ष 2017-18 में 20645.30 लाख गुणवत्ता युक्त मत्स्य बीज मत्स्य पालकों को रोजगार वृद्धि के लिए उपलब्ध कराया गया।
- ◆ वर्ष के प्रथम त्रैमास में गत वर्ष की अपेक्षा 2.52 लाख मैट्रिक टन अधिक मत्स्य उत्पादन।
- ◆ 275 मत्स्य कृषकों को निशुल्क विभागीय प्रशिक्षण। 10 मोबाइल फिश पार्लर इकाईयों की स्थापना व 200 हे० निष्प्रयोज्य जलमग्न क्षेत्र को मत्स्य पालन से आच्छादन का लक्ष्य।
- ◆ मत्स्य पालकों को मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित करने के लिए वर्ष 2017-18 में प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत 2,00,000 लाभार्थियों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य।
- ◆ मत्स्य उत्पादन क्षमता का विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए 750 नर्सरियों के निर्माण का लक्ष्य। 20 नर्सरियों का निर्माण पूर्ण।
- ◆ 11 राजकीय मत्स्य प्रक्षेत्रों पर मत्स्य पालन हेतु जलापूर्ति के लिए 11 सोलर पम्पों की स्थापना।
- ◆ भारत सरकार के सहायता से संचालित "ब्ल्यू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट फार फिशरीज सेक्टर" योजना के अन्तर्गत 19.591 हे० नये तालाबों का निर्माण, 293.08 हे० तालाबों का सुधार, 15.60 हे० पर मत्स्य बीज रियरिंग इकाई की स्थापना तथा 03 आटोरिक्शा विद आइसबाक्स उपलब्ध कराये गये।



स्वागत है अप्रवासी भारतीयों का



- ◆ विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित "नो इण्डिया प्रोग्राम" (के.आई.पी.) में पार्टनर स्टेट के रूप में सहभागिता करने हेतु सहमति। अप्रवासी भारतीयों के शिकायत निवारण हेतु वेबसाईट/वेब-पोर्टल <http://upnrigrs.in> का निर्माण। प्रदेश के कामगारों को विदेश में रोजगार दिलाने हेतु चयन प्रक्रिया का संचालन रिक्रूटिंग एजेन्सी की ब्रान्च आफिस गाजियाबाद तथा मेरठ द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। गोरखपुर, वाराणसी तथा लखनऊ में रिक्रूटिंग एजेन्सी की शाखा शीघ्र खोली जायेगी। संकट में फंसे भारतीयों की सहायता हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति।

बाह्य सहायतित परियोजना

- ◆ एशियन विकास बैंक के वित्त पोषण से 2782 करोड़ रू० लागत की उत्तर प्रदेश जिला मुख्य सड़क विकास परियोजना का एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित। परियोजना 12 जिलों में संचालित की जायेगी, जिसमें 431 किलोमीटर के सड़क निर्माण कार्य कराये जायेंगे।

बाढ़ से राहत: सरकार ने निभाई जिम्मेदारी



- ◆ नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों से अतिशय वर्षाजल छोड़ने के कारण प्रदेश के 24 जनपदों में इस वर्ष भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा। कुल 2922684 जनसंख्या प्रभावित हुई तथा 118 जनहानि का सामना करना पड़ा।
- ◆ बाढ़ राहत मद में रू. 454.40 करोड़ धनराशि का प्रावधान किया गया है। 15 सितम्बर तक जनपदों को कुल रू. 263.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।
- ◆ जिन लोगों की बाढ़ के कारण मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा कुल रू. 4.4 लाख की अहेतुक सहायता ऐसे प्रत्येक प्रकरण में देने की व्यवस्था की गई।
- ◆ 314155 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई तथा लगभग 25 हजार पक्के एवं कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए।
- ◆ सरकार के द्वारा बाढ़ से प्रभावित सभी जनपदों में भू-राजस्व देयों की वसूली 31 मार्च, 2018 तक स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।
- ◆ पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बाढ़ प्रभावित जनपदों अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, पीलीभीत, श्रावस्ती और सीतापुर का नाव से दौरा कर राहत कार्यों का पर्यवेक्षण किया तथा त्वरित गति से राहत सामग्री का वितरण सुनिश्चित किया।





- ◆ 389 शिविरों का संचालन किया गया जिनमें 282581 लोगों ने आश्रय प्राप्त किया। एन. डी.आर.एफ. की 28 टीमों, 217 मोटर बोट, 4963 नावों एवं पी.ए.सी. फ्लड बटालियन की 30 टीमों खोज एवं बचाव कार्यों में लगी रही। 1948857 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया गया।
- ◆ 654273 पैकेट राहत सामग्री का वितरण किया जा चुका है जिनमें 16 प्रकार की लगभग 50 किलोग्राम घरेलू उपयोग की सामग्री रखी गई है।
- ◆ मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ नियंत्रण परिषद स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। स्थायी समिति की यह बैठक 21 वर्ष बाद आयोजित हुई थी। उन्होंने कहा कि भविष्य में स्थायी समिति की बैठक प्रत्येक दशा में दिसम्बर तक सुनिश्चित करायी जाए, जिससे बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय से धनराशि की व्यवस्था बजट में की जा सके।



आई.टी.-इलेक्ट्रॉनिक्स : खुले सम्भावनाओं के द्वार



- ◆ सभी शासकीय विभागों में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू।
- ◆ विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 55000 ई-टेण्डर प्रकाशित।
- ◆ लगभग 28000 नए निविदादाताओं द्वारा ई-टेण्डर में प्रतिभाग हेतु डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त कर ई-टेण्डर पोर्टल पर पंजीयन।
- ◆ 12000 से अधिक अधिकारियों को ई-टेण्डर प्रशिक्षण।
- ◆ 50 से अधिक विभागों द्वारा नोडल अधिकारी नामित करते हुए ई-टेण्डरिंग प्रणाली से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण।
- ◆ इन्क्यूबेटर के अन्तर्गत लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट के सामने यूपीडीपीएल की भूमि का चयन कर लगभग एक लाख वर्गफीट भूमि पर देश के सबसे बड़ा इन्क्यूबेटर की स्थापना प्रस्तावित।
- ◆ साइबरहाइट्स भवन विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के सप्तम तल पर स्थित लगभग 372 वर्गमीटर 60 सीटर नव-उद्यमी उत्प्रेरक केन्द्र (कन्क्यूबेटर) संचालित है। 10 स्टार्ट अप्स कार्यरत है।

आगरा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना

- ◆ एस.टी.पी.आई, द्वारा चहारदीवारी निर्माण कार्य पूर्ण।
- ◆ मुख्य भवन निर्माण के लिए कान्ट्रैक्टर का चयन। लगभग 2000 से अधिक नव-उद्यमियों एवं युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।



मेरठ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना

- ◆ मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माण हेतु मानचित्र पर अनुमोदन।
- ◆ मुख्य भवन निर्माण के लिए कान्ट्रैक्टर का चयन।
- ◆ लगभग 2000 उद्यमियों एवं युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

गोरखपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना।

- ◆ गोरखपुर में बड़गहन क्षेत्र में 3.5 एकड़ भूमि का हस्तान्तरण विलेख आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के पक्ष में करा लिया गया है।
- ◆ भूमि एस.टी.पी.आई. को उपलब्ध करा दी गई। एस.टी.पी.आई. द्वारा निर्माण कार्य किये जायेंगे।

मथुरा में हिन्दुस्तान कालेज में नव-उद्यमी उत्प्रेरक केन्द्र (इन्क्यूबेटर) की स्थापना।

- ◆ मथुरा में 5000 वर्गमीटर में नव-उद्यमी उत्प्रेरक केन्द्र (इन्क्यूबेटर) की स्थापना की जा रही है।



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी



- ◆ विज्ञान लोकप्रियकरण हेतु 15000 विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षकों को स्वच्छ पेयजल की गुणवत्ता, परीक्षण, उपयोग और सुरक्षित भंडारण तथा जल स्रोतों के संरक्षण पर जागरूक किया गया।
- ◆ चिकित्सा, औषधि, कृषि इत्यादि क्षेत्र की 25 शोध परियोजनाओं का वित्त पोषण।
- ◆ सोनभद्र जनपद में दो खनन क्षेत्रों का उपग्रहीय आंकड़ों के माध्यम से चिन्हांकन तथा सजरा स्तर पर डिजिटल डाटाबेस तैयार किया गया।
- ◆ गोरखपुर एवं बलिया जनपदों में गत वर्षों में बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर बाढ़ प्रबंधन हेतु संबंधित विभागों हेतु मानचित्रों का सृजन किया गया।
- ◆ बाढ़ आने पर जनपदों का उपग्रह आधारित मानचित्र सम्बन्धित जिला प्रशासन को नियमित रूप से भेजा गया।



जरूरतमंदों के साथ सरकार



प्रदेश सरकार ने गम्भीर रोगों से पीड़ित विभिन्न जिलों के जरूरतमंद लोगों की मदद के हर संभव प्रयास किये हैं। अब तक 5298 जरूरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 69 करोड़ 41 लाख 17 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

- ♦ मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज पर हुये व्यय के कारण गम्भीर रोगों से ग्रसित तीन जरूरतमंद लोगों को 3 लाख 30 हजार रुपये की सहायता दी गई।
- ♦ किडनी ट्रांसप्लाण्ट के बाद इलाज के लिए 2 जरूरतमंद लोगों को 3 लाख 60 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।
किडनी ट्रांसप्लाण्ट के लिए 63 जरूरतमंद लोगों को 2 करोड़ 36 लाख 9 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।
- ♦ हृदय से सम्बन्धित रोगों के उपचार के लिए 979 जरूरतमंद लोगों को 8 करोड़ 70 लाख 43 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।



- ♦ किडनी की बीमारी के इलाज के लिए 876 जरूरतमंद लोगों को 15 करोड़ 77 लाख 60 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।
- ♦ कैंसर के इलाज के लिए 2102 लोगों को 29 करोड़ 52 लाख 57 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।
- ♦ शरीर की किसी गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए 1273 जरूरतमंद लोगों को 13 करोड़ 29 लाख 97 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।
- ♦ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनपद लखीमपुर खीरी के धौहररा कस्बे के निवासी श्री सुरेन्द्र चौरसिया की अत्यन्त कमजोर आर्थिक स्थिति व

पारिवारिक परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

- ♦ जनपद सहारनपुर के अलीपुर ग्राम की बालिका ईशू कुमारी द्वारा ट्विटर के माध्यम से अपने पिता के उपचार हेतु किए गए मदद के अनुरोध का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी को श्री अरुण कुमार के समुचित उपचार की अविलम्ब व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।





माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के प्रथम उत्तर प्रदेश आगमन पर भव्य नागरिक अभिनंदन ।
(14 सितंबर, 2017)

